LOK SABHA

Friday, July 14, 1967/Asadha 23, 1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Tractor Factories

+

*1141. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bharat Singh Chauhan:
Shri Ranjeet Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether due to heavy demand of tractors in the country, some tractor factories are proposed to be set up;

(b) if so, the location of the factories with the capacity thereof; and

(c) whether these will be set up in private or public sector?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Raghunath Reddi): (a) to (c). There are five factories in the private sector manufacturing agricultural tractors in the range 25 to 50 HP. Their aggregate licensed capacity is 30,000 Nos. per year. Two of these factories are located at Faridaad and one each at Bombay, Baroda and Madras. A proposal to set up a factory in the Public Sector for the manufacture of tractors below 20 HP with a capacity of 12,000 Nos. per year is under consideration.

श्री शारदानन्द : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान इस बात की ओर गया है कि जब कम कीमत से बनने वाले ट्रैक्टरों की खपत इस देश में ज्यादा होगी तो उनको बनाने के लिये उत्तर प्रदेश में कोई कराखाना खोला जाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि अभी सवाल के जवाब में बतलाया गया है यह पांच प्राइवेट सैक्टर के कारखाने जो हैं वह ट्रैक्टर बना रहे हैं। हम को 20 हार्स पावर से कम के करीब 12 हजार ट्रैक्टरों की जरूरत है। इसके लिये हमने जेकोस्लोवाकिया से रिपोर्ट मंगाई है। उन्होंने यह फैसला किया है कि अगर यह फैक्टरी चलाई जाये तो उत्तर प्रदेश में वह हो।

श्री शारदानन्द : सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के लिये अब तक सरकार ने किन-किन देशों से परामर्श किया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अभी मई के महीने में इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, उस पर गौर किया जा रहा है।

श्री भारत सिंह चौहान : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र के अन्दर किन किन प्रान्तों से इन कारखानों को स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र आये हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : बहुत से प्रान्तों से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी—

बिहार से, केरल से, मद्रास से, गुजरात से राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। इन सब बातों पर गौर करके, चूंकि कुछ ट्रैक्टरों का काम गुजरात में हो रहा है मद्रास और बम्बई में भी हो रहा है, इसलिये सोचा गया कि इंडो गैन्जेटिक बेल्ट जो है, जहां इसकी ज्यादा जरूरत है, वहां इसको शुरू किया जाये। जो दो तीन जगह बतलाई गई हैं हमने वह अपने एक्सपर्टस को दिखलाई थीं और उन्होंने गौर करके फैसला दिया है कि अगर यू० पी० में हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : म जानना चाहता हूं कि सरकार को कितने ट्रैक्टरों की जरूरत है और यह कारखाना खोलने के बाद हम को क्या और भी ट्रैक्टर बाहर से मंगाने पड़ेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : फोर्थ फाइव इयर प्लैन में हम को 40 हजार ट्रैक्टरों की जरूरत है। अभी जिन प्राइवेट कम्पनियों के पास लाइसेंस हैं वह 30,000 ट्रैक्टर बनायेंगी पब्लिक सैक्टर में और 12 हजार ट्रैक्टरों का इन्तजाम किया जा रहा है। उसके बाद हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा।

श्री क० ना० तिवारी : पहले जो किस्म किस्म के ट्रैक्टर हमारे देश में बाहर से आये उनके स्पेअर पार्टस न मिलने की वजह बेकार पड़े हैं जो चेकोस्लोवाकिया और रशिया से आये हुए ट्रैक्टर्स भी स्पेअर पार्ट्स न होने की वजह से बेकार पड़े हुए हैं। इस बात आप के पास जो ट्रैक्टर बनाने की स्कीम है उसके अलावा क्या कोई ऐसा भी कार्यक्रम है कि वह पार्टस यहां मंगाये जांय ताकि बेकार पड़े हुए ट्रैक्टर काम में आ जांय और ट्रैक्टर्स बाहर से न मंगवाने पड़ें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसके ऊपर गौर किया गया है और एक कमेटी बनाई गई है कि हमारे जो एन० ए० एम० सी० व हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कारपोरेशन है क्या उनमें ऐसी कपैसिटी है कि जिन कंपोनेन्ट्स पार्टस की जरूरत है वह उनको बना सकते हैं ? कमेटी इस पर गौर करके जल्दी से जल्दी इसका इन्तजाम करेगी।

Shri S. Kandappan : Keeping in view the demand for different types of tractors and power tillers in various States according to the requirements as per their local conditions prevailing in different States, I would like to know whether the Government have consolidated the requirements and whether they will be allocating sufficient foreign exchange on a priority basis required for the tractor factories and also the components thereof.

Shri F. A. Ahmed : As I have pointed out, the Government have taken into consideration all these factors. As the Hon. Member is aware, this was not in the priority list. But now tractors have been included in the priority list and all the help of foreign exchange required for the components or for the maximum utilisation of the capacity given to the private sector will be given.

श्रीमती जयाबेन शाह : श्री क० ना० तिवारी ने सवाल पूछा था उसके पहले हिस्से में यह था कि आज देश में 20 हजार ट्रैक्टर स्पेअर पार्टस न होने की वजह से आइडल पड़े हैं। मैं पहली बात यह जानना चाहती हूं कि क्या गवर्नमेंट यह सोच रही है कि जिन के स्पेअर पार्टस पहले मिल जाय वह ट्रैक्टर्स पहले इस्तेमाल किये जांय ? दूसरी बात यह कि आप ने 12 हजार ट्रैक्टर बनाने की बात कही है उसके बजाय अगर जो ट्रैक्टर्स कई सालों से बेकार पड़े हुए हैं उन को ठीक कर लिया जाये तो हमारा काम चल सकता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसके लिये कदम उठाये जायेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस के लिये सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो यह कि जिन फारेन कम्पोनेन्ट पार्टस की जरूरत

हैं उन के लिये फारेन एक्सचेंज.....

श्रीमती जयाबेन शाह : जो नई फैक्ट्री होगी उसके लिये भी तो फारेन एक्सचेंज की जरूरत होगी। इस के लिये फारेन एक्सचेंज की दिक्कत की बात न कीजिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कम्पोनेन्ट पार्टस के लिये अगर फारेन एक्सचेंज की जरूरत होगी, जिसके बिना जो ट्रैक्टर मौजूद हैं और नहीं चलते हैं, तो वह फारेन एक्सचेंज हम देंगे। दूसरे यह कि बजाय इसके कि हम फारेन कंट्रीज पर डिपेन्ड करें अगर हम एन० ए० एम० सी० या हेवी इंजीनिअरिंग इंडस्ट्रीज कारपोरेशन में कम्पोनेन्ट पार्ट्स बनवा सकें तो बनवायें। इसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं।

Shri Hem Barua: May I know the proportion of foreign collaboration, if any, or the foreign components where the Government propose to allow for these factories whether in the public sector or in the private sector?

Shri F. A. Ahmed: It varies from factory to factory. I may inform the Hon. Member that so far as Massey Ferguson is concerned, the indigenous content is 68 per cent, International Harvester—59.5 per cent, Hindustan—80 per cent for 50 H.P. and 50 per cent for 30 H.P., Escorts—53.7 per cent and Eicher—57 per cent. So far as the public sector is concerned, practically 80 per cent of the requirement will be indigenous.

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि हालांकि जो कमिशन मुकर्रर किया गया है उसने गैन्जेटिक प्लेन में फैक्ट्री खोलने की सलाह दी है, लेकिन क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में लाखों गांव हैं, और क्या सारे भारतवर्ष के लिये सिर्फ चालीस हजार ट्रैक्टरों से काम चल जायेगा ? मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में दो फैक्टरियां हों जिन से हमारा पूरा काम चल सके।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस पर तो गौर किया जाता ही है। जितने ट्रैक्टरों की जरूरत है आहिस्ता-आहिस्ता उन को हम हर प्लैन में बढ़ाते रहेंगे। जैसा मैंने बतलाया चौथी प्लैन में हमें 40 हजार ट्रैक्टरों की जरूरत होगी। उनको बनाने की कोशिश की जायेगी।

भिलाई इस्पात कारखाने में रेल की पटरियों का निर्माण

\+

*1142. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में रेलों की पटरियों के निर्माण में मिश्रधातु का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) Yes, Sir. This is the normal process of making rail steel.

(b) and (c). An enquiry was made regarding the deficiency in carbon and manganese content of the steel used for manufacturing rails at Bhilai and it was found that there was a case of a mix-up of blooms of different types of steel on 22nd July, 1966. A Committee of enquiry was constituted to identify the possible cause of this mix-up and to make recommendations to